Toppersnotes
Unleash the topper in you

JPSC

State Civil Services

Jharkhand Public Service Commission

(Preliminary & Main)

पेपर - 3

भारत एवं झारखण्ड की अर्थव्यवस्था

SIERRA INNOVATIONS

JPSC

भारत एवं झारखण्ड की अर्थव्यवस्था

विषय-सूची

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	राष्ट्रीय आय एवं उत्पाद	1
2.	मुद्रा स्फीति भविष्य के बाजार वित्तिय समावेशन	17
3.	वित्त बाजार	28
4.	लोक वित्त	40
5.	वस्तु व सेवाकर, कर टालना	52
6.	भारतीय रिजर्व बैंक व बैंकिग क्षेत्र	57
7.	भारत के वैदेशिक क्षेत्र	73
8.	विदेशी व्यापार नीति	78
9.	अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन	87
10.	समावेशी विकास	97
11.	भारतीय कृषि से संबन्धित विभिन्न महत्वपूर्ण बिन्दु	101
	• कृषि सब्सिडी	101
	• पशुपालन का अर्थशास्त्र	128
	• भूमि सुधार	132
12.	सरकारी बजट से जुडे विभिन्न पहलू व अन्य अवधारणायें	146
13.	आधारभूत संरचना एवं निवेश मंडल	160
14.	बौद्धिक सम्पदा अधिकार	170
15.	आर्थिक उदारीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव	175
16.	गरीबी	185
17.	बेरोजगारी	191

18. खाद्य सुरक्षा 195
19. वैश्विक परिदृश्य मे भारत 201
20. झारखण्ड की अर्थव्यवस्था एवं जनसंख्या 203
21. झारखण्ड में भूमि सुधार से संबंधित कानून 207
22. झारखण्ड की प्रमुख नीतियाँ 217
23. केन्द्र सरकार की विभिन्न जन कल्याण कारी योजनायें 250

राष्ट्रीय आय एवं उत्पाद
National income & Product

प्रस्तावनाः–

अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा है । अर्थशास्त्र एवं किसी अर्थव्यवस्था की समझ के लिए राष्ट्रीय आय की गणना से जुडी अवधारणों का स्पष्ट होना आवश्यक है । वैसे तो इसका पता सामान्य तौर पर देश और वहां के लोगों की खुशहाली और उनकी प्रसन्नता से लगाते है । यह तरीका आज भी इस्तेमाल होता है हालाँकि हम यह जान चुके है कि आय से किसी भी समाज के बेहतर और कुशल होने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है । इस राय के पीछे कई वजहें भी हैं, जब 1990 के शुरूआती सालों में मानव विकास सूचकांक की शुरूआत हुई । इस सूचकांक में किसी भी देश में प्रति व्यक्ति आय को काफी प्राथमिकता दी गई थी । लेकिन समाज में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति तभी बेहतर होती है जब इन क्षेत्रों में भी बडे पैमाने पर निवेश किया जाता हो । यही वजह है कि विकास या मानव विकास का केंद्र बिंदु आय को माना जाता है ।

अर्थात् –

- किसी देश में होने वाली सभी आर्थिक गतिविधियों का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है, अर्थात् अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों की आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है ।

<u>सकल घरेलू उत्पाद **(GDP)**</u> **:-** एक वित्त में किसी देश के निवासियों द्वारा देश की आर्थिक सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जी.डी.पी. कहलाता है ।

<u>अंतिम वस्तु एवं सेवा</u>–

- उत्पादन प्रक्रिया से बाहर आने वाली वस्तुएँ दो प्रकार की होती है ।
  (1) <u>मध्यस्थ वस्तुएँ</u>– ऐसी वस्तुएँ जो किसी अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में काम में ली जाती हैं, मध्यस्थ वस्तुएँ कहलाती है अर्थात् यह वस्तुएँ अंतिम उपभोक्ता द्वारा उपभोग में नहीं ली जाती । जैसे– कार का इंजन ।

  (2) <u>अंतिम वस्तुएँ</u> – ऐसी वस्तुएँ जिनका उपभोग अंतिम उपभोक्ता द्वारा किया जाता है अर्थात् इनमें उत्पादन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी होती है और उत्पादन संभव नहीं होता है । अन्तिम वस्तुएँ कहलाती हैं । जैसे – कार
- दोहरी गणना से बचने के लिए मध्यस्थ वस्तुओं को छोड दिया जाता है और केवल अंतिम वस्तुओं को लिया जाता है ।
  भारत की जी.डी.पी. गणना अंतर्राष्ट्रीय प्रचलन के अनुरूप बनाने के लिए इसे सकल मूल्य संवर्द्धन (GVA) आधारित बनाया गया ।

  (1) GVA_{fc} = Rent + Interest + Wages + Profit

  (2) $GVA_{bp} = GVA_{fc} +$ उत्पादन कर – उत्पादन सब्सिडी

  (3) $GDP_{mp} = GVA_{bp} +$ उत्पाद कर – उत्पाद सब्सिडी

- वह मूल्य जिस पर सरकार द्वारा अंतिम उपभोक्ता से कर वसूले जाते है, आधार मूल्य कहलाता है ।

वित्त वर्ष :-

- 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 12 महीने की अवधि वित्त वर्ष कहलाती है ।
- वित्त वर्ष को परिवर्तित करने की संभावना ढूंढने के लिए निम्न कमेटियों का गठन किया गया ।
  (1) बेल्बी आयोग
  (2) एल.के. झा समिति
  (3) दार्मिश वाचा समिति
  (4) शंकर आचार्य समिति (हाल ही में निर्मित)

उत्पादन कर – उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगने वाला कर । जैसे– कच्चे माल पर लगने वाला कर
उत्पादन सब्सिडी– उत्पादन प्रक्रिया के दौरान मिलने वाली सब्सिडी उत्पादन सब्सिडी कहलाती है । जैसे– स्वदेशी कच्चे माल पर सब्सिडी
उत्पाद कर– अंतिम उत्पाद कर प्रति इकाई पर लगाया जाने वाला कर । जैसे–उत्पाद शुल्क, गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स आदि । यह कर अंतिम उपभोक्ता से वसूला जाता है जबकि उत्पादन कर उत्पादक से लिया जाता है ।
उत्पाद सब्सिडी – अंतिम उत्पाद पर उपभोक्ता को दी जाने वाली सब्सिडी जैसे – बैट्री कार पर सब्सिडी ।

जीडीपी के विभिन्न उपयोग निम्न है :-

1. जी.डी.पी. में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर (वृद्धि दर) है जैसे – किसी देश की जी.डी.पी. रू. 107 है और यह बीते साल से रू. 7 ज्यादा है तो उस देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7 प्रतिशत है । जब हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को ग्रोइंग इकॉनोमी कहते है तो मतलब यह होता है कि देश की आय परिमाणात्मक रूप से बढ रही है ।
2. यह परिमाणात्मक दृष्टिकोण है । इसके आकार से देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है । लेकिन इससे देश के अंदर उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता के स्तर का पता नही चल पाता है ।
3. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों का तुलनात्मक विश्लेषण इसके आधार पर ही किया जाता है ।

शुद्ध घरेलू उत्पाद **(NDP)** :-

- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में से मूल्य ह्रास घटाकर इसकी गणना की जाती है ।
- विभिन्न देशों में मूल्य ह्रास की गणना अलग–अलग विधियों से की जाती है । इसलिए शुद्ध घरेलू उत्पाद का आधार प्रत्येक देश में समान नहीं होता ।
- इस कारण शुद्ध घरेलू उत्पाद का उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाता है ।

अन्य शब्दों में :-

शुद्ध घरेलू उत्पाद (NDP), किसी भी अर्थव्यवस्था का वह जीडीपी है, जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती को घटाकर प्राप्त किया जाता है । वास्तव में जिन संसाधनों द्वारा उत्पादन किया जाता है उपयोग के दौरान उनके मूल्य में कमी हो जाती है जिसका मतलब उस सामान का घिसने (Depreciation) या टूटने–फूटने से होता है । इसमें मूल्य कटौती की दर सरकार निर्धारित करती है । भारत में यह फैसला केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है । यह एक सूची जारी करता है जिसके मुताबिक विभिन्न उत्पादो में होने वाली मूल्य कटौती (घिसावट) की दूरी तय होती है ।
इस तरह से देखें तो NDP = GDP – घिसावट

ऐसे जाहिर है कि किसी भी वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था में एनडीपी हमेशा उस साल की जीडीपी से कम होगी । अवमूल्यन की शून्य करने का कोई भी तरीका नही है । लेकिन मानव समाज इस अवमूल्यन को कम से कम करने के लिए कई तरकीबें निकाल चुका है ।

मूल्य ह्रास :- उत्पादन प्रक्रिया के दौरान, उत्पादन में प्रयोग में ली गई सम्पत्तियों व मशीनों में घिसावट होती है, इस कारण इनके मूल्य में आयी कमी मूल्य ह्रास कहलाती है ।

शुद्ध घरेलू उत्पाद का अलग-अलग प्रयोग निम्न है :-

(1) घरेलू इस्तेमाल के लिए इसका इस्तेमाल घिसावट के चलते होने वाले नुकसान को समझने के लिए किया जाता है । इतना ही नही खास समयावधि के दौरान उद्योग धंधे और कारोबार में अलग-अलग क्षेत्र की स्थिति का अंदाजा भी इससे लगाया जा सकता है ।

(2) अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धि को दर्शाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ।

लेकिन एनडीपी का इस्तेमाल दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए नहीं किया जाता है । ऐसा क्यों है ? इसकी वजह है कि दुनिया की अलग-अलग अर्थव्यवस्थाएँ अपने यहाँ मूल्य कटौती की अलग-अलग दरें निर्धारित करती है । यह दर मूल रूप से तार्किक आधार पर तय होती है ।

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (**GNP**) :-

किसी अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) उस आय को कहते है जो जीडीपी में विदेशों से होने वाली आय को जोडकर हासिल होता है । इसमें देश की सीमा से बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधियों को भी शामिल किया जाता है । या,

सकल राष्ट्रीय उत्पाद **(GNP)** :- एक वित्त वर्ष के दौरान देश के सभी नागरिकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है ।

(1) $GNP_{mp} = GDP_{mp}$ + Net factor Income from abroad (NFIFA)

(2) NFIFA = Income of Indian Citizen outside India – Income earned by foreigner in India

विदेशों से होने वाली आय में निम्नांकित पहलू शामिल हैं :-

1. निजी प्रेषण (Private Remittances)
2. विदेश कर्जे पर ब्याज (Interest of The External Loans)
3. विदेश अनुदान (External Grants)

सामान्यतः फार्मूले के मुताबिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद $ विदेशों से होने वाली आय के बराबर है, लेकिन भारत के मामले में विदेशों से होने वाली आमदनी के बदले हानि होती है । लिहाजा भारत का हमेशा विदेशों से होने वाली आमदनी के बराबर होता है

सकल राष्ट्रीय उत्पाद के विभिन्न उपयोग निम्न प्रकार है –

i. इससे राष्ट्रीय आय के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) दुनिया के देशों की रैंकिंग तय करता है । इसके आधार पर आईएमएफ देशों को उनकी क्रय शक्ति तुल्यता (PPP) के आधार पर रैंक करता है ।
ii. राष्ट्रीय आय को आँकने के लिहाज से सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की तुलना में विस्तृत पैमाना है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की परिमाणात्मक के साथ-साथ गुणात्मक तस्वीरें भी पेश करता है । किसी भी अर्थव्यवस्था की आंतरिक के साथ-साथ बाहरी ताकत को भी बताता है ।
iii. यह किसी भी अर्थव्यवस्था के पैटर्न और उसके उत्पादन के व्यवहार को समझने में काफी मदद करता है । यह बताता है कि बाहरी दुनिया किसी देश के खास उत्पाद पर कितने निर्भर है और वह उत्पाद दुनिया के देशों पर कितना निर्भर है ।

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी (NNP) :-

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) में से मूल्य कटौती को घटाने के बाद जो आय बचती है, उसे ही किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) कहते है ।

या

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद **(NNP)** :-

- इसकी गणना के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाया जाता है ।
- भारत में कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय माना जाता है ।
- बाजार मूल्य/वर्तमान मूल्य पर राष्ट्रीय आय को शुद्ध राष्ट्रीय आय (NNI) कहा जाता है ।
- $NNP_{mp} = GNP_{mp}$ – मूल्य ह्रास (Depreciation)
- $NNP_{fc} = NNP_{mp}$ – अप्रत्यक्ष कर + सब्सिडी
- प्रति व्यक्ति आय = $\frac{\text{राष्ट्रीय आय}}{\text{जनसंख्या}} \Big/ \frac{NNP_{fc}}{\text{जनसंख्या}}$
- $GDP_{cp} = GDP_{mp}$ – मुद्रास्फीति (CP = स्थिर मूल्य)
- GDP_{cp} को वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है ।
- बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद को नाममात्र का सकल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है ।

$$\text{GDP Deflator} = \frac{\text{Nomial GDP}}{\text{Real GDP}} \Big/ \frac{\text{GDPmp}}{\text{GDPcp}}$$

शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के विभिन्न उपयोग निम्न प्रकार है :-

i. यह किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय (National Income) (NI) है । यद्यपि जी.डी.पी., एन.डी.पी. और जी.एन.पी. सभी राष्ट्रीय आय ही है लेकिन नेशनल इनकम (NI) के तौर पर नहीं लिखा जाता ।
ii. यह किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को आंकलित करने का सबसे बेहतरीन तरीका है ।
iii. जब हम NNP को देश की कुल आबादी से भाग देते है । तो उससे देश की प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है, यह प्रतिव्यक्ति सालाना आय होती है, यहाँ एक मूल बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि यह अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती है । ऐसे में किसी देश में मूल्य कटौती की दर ज्यादा होने पर प्रति व्यक्ति की आय में कमी होती है ।

- भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केन्द्रीय सांख्यिकी संघठन द्वारा की जाती है ।
- राष्ट्रीय आय के लिए आकडों का संकलन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) और केन्द्रीय सांख्यिकी संघठन (CSO) द्वारा किया जाता है ।
- यह दोनों संस्थाएँ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) के अन्तर्गत कार्य करती है ।
  (1) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MOSPI = Ministry of Statistics & Program Implementation)

  (2) राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन (NSSO = National Sample Survey Office/Organization)

- राष्ट्रीय आय की गणना चार मूल्यों पर आधारित होती है ।
  (1) कारक लागत
  (2) <u>बाजार मूल्य</u> – वह मूल्य जिस पर अंतिम उपभोक्ता द्वारा वस्तुएँ खरीदी जाती है बाजार मूल्य कहलाता है । इसे वर्तमान मूल्य भी कहा जाता है ।
  (3) <u>आधार मूल्य</u> –
    – राष्ट्रीय आय की तुलना के लिए किसी एक वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है ।
    – भारत में 2011–12 को आधार वर्ष घोषित किया गया है ।
    – किसी वस्तु का आधार वर्ष का मूल्य आधार मूल्य कहलाता है ।
  (4) <u>स्थिर मूल्य</u>–
    – यदि बाजार मूल्य में से मुद्रास्फीति का प्रभाव हटा दिया जाये तो वह स्थिर मूल्य कहलाता है ।
    – राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्न अवधारणाएँ प्रचलित है– सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल देशीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद

<u>मौद्रिक राष्ट्रीय आय</u> (Nominal National Income)

इसे प्रचलित या चालू मूल्यों पर राष्ट्रीय आय (National Income at Current Price) भी कहा जाता है। इसमें आधार वर्ष की कीमतों का प्रयोग नहीं किया जाता। ऐसी स्थिति में उत्पादन को लेकर वस्तुस्थिति का पता नहीं लग पाता । अतः इस राष्ट्रीय आय को अधिक महत्व नहीं दिया जाता ।

इसे निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है–

$$GNP\ Deflator = \frac{Nominal\ GNP}{Real\ GNP}$$

GNP Deflator – सकल राष्ट्रीय उत्पाद अपस्फीतिकारक
Nominal GNP – नाममात्र का सकल राष्ट्रीय उत्पाद
Real GNP – वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद

यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद अपस्फीतिकारक को प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त करना हो तो इसके मूल्य को 100 से गुणा कर दिया जाता है । उदाहरण के लिए यदि किसी वर्ष हेतु सकल राष्ट्रीय उत्पाद अपस्फीतिकारक का मूल्य 1.25 हो तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया जाएगा एवं इसका मान 125 आ जाएगा । इसका अभिप्राय यह होगा कि चालू मूल्य पर जीएनपी वास्तविक जीएनपी के मूल्य का 125% होगा ।

संवृद्धि एवं विकास **(Growth and Development)**

संवृद्धि (Growth) मात्रात्मक होती है तथा राष्ट्रीय आय अथवा उत्पादन में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है । विकास गुणात्मक तथा जीवन की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है ।

जीवन के अच्छे गुणवत्ता में आय अथवा ग्रोथ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । लेकिन आय अथवा ग्रोथ द्वारा जीवन की गुणवत्ता को पूर्ण स्पष्ट नहीं किया जा सकता है । कुछ अन्य बातों की आवश्यकता होती है जैसे – ज्ञान, अच्छा स्वास्थ्य आदि ।

जीवन की गुणवत्ता **(Quality of Life)**

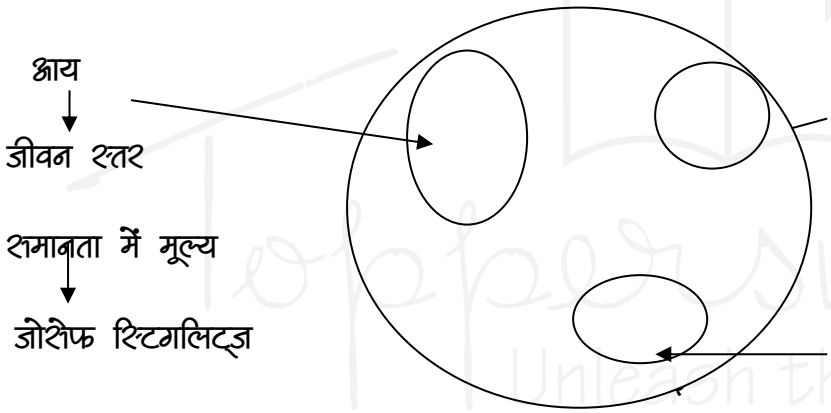

संवृद्धि तथा विकास एक–दूसरे के विरोधी नहीं है । यह एक–दूसरे के पूरक होते है, जैसे– यदि एक राष्ट्र में अच्छी संवृद्धि है तो उसमें कर संग्रह का स्तर ऊँचा होगा, जिसके द्वारा संबंधित सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य पर सामाजिक व्यय बढा सकती है ।

इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के एक रिसर्च के अनुसार यदि साक्षरता की दर को 20% से बढा दिया जाता है तो संबंधित राष्ट्र की संवृद्धि दर में 5% तक की बढोतरी हो सकती है ।

मानव विकास सूचकांक **HDI (Human Development Index)**

विकास गुणात्मक होता है इसलिए उसे गणितीय रूप से नहीं मापा जा सकता है लेकिन मोटे रूप में इसकी स्थिति एवं दिशा को समझने के लिए यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया जाता है ।

मानव विकास सूचकांक के निर्माण में पाकिस्तान के स्वर्गीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर महबूब उल हक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । हालाँकि उनके लिए प्रोफेसर अमर्त्य सेन की वास्तविक गरीबी की संकल्पना प्रेरणा का स्रोत रही है । प्रोफेसर अमर्त्य सेन के अनुसार क्षमताओं का अभाव गरीबी है । उनके अनुसार विकास स्वतंत्रता प्रदायक होता है और एक क्षमतावान व्यक्ति ही स्वतंत्र हो सकता है ।

मानव विकास सूचकांक के निर्माण में निम्न आयामों तथा सूचकों का प्रयोग किया जाता है ।

1- आयाम **(Dimension)**	सूचक **(Indicators)**
दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन	जीवन प्रत्याशा (Life Expeciancy) 168 वर्ष

2. ज्ञान
   - स्कूल के औसत वर्ष (Mean years of schooling) (5.4 वर्ष)
   - स्कूल के प्रत्याशित वर्ष (11.7 वर्ष)

3. जीवन स्तर:– वास्तविक सकल राष्ट्रीय आय (Real per capita GNI)
   यू.एस.डी. (संयुक्त राज्य) (USD: United State)
   Dollors: PPP
   आधार : $5497

नोट :-

1. <u>सकल राष्ट्रीय आय GNI (Gross National Income)-</u>
   को निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग–
   GNP_{mp} = Indirect taxes + Subsidy
   GNP_{fc}= GNI

2. यह ध्यान देने योग्य है कि 2010 से पहले UNDP द्वारा GDP_{fc} का प्रयोग किया जाता था लेकिन 2010 में यूएनडीपी द्वारा यह कहा गया कि भूमंडलीकरण के कारण कई राष्ट्रों का जीवन स्तर विदेशी साधन आय से प्रभावित हो रहा है । इसलिए विदेशी साधन आय का ध्यान रखना जरूरी है । अतः उसके द्वारा 2010 में जी. एन. आई. के प्रयोग को शुरू कर दिया गया ।

3. विनिमय दर (Exchange Rate) दो प्रकार की होती है ।
   - चालू–विनिमय दर ।
   - क्रय शक्ति आधारित विनिमय दर ।

   चालू विनिमय दरें मुद्राओं की क्रय शक्ति में अंतर को ठीक से प्रदर्शित नहीं कर पाती । जैसे – अमेरिकन डॉलर की माँग केवल उसकी क्रय शक्ति को लेकर नहीं होती है । उसकी माँग निवेश एवं अन्य कारणों से भी होती है, जिसके चलते उसकी विनिमय दर काफी ऊँची जा सकती है । ऐसी अवस्था में क्रय शक्ति आधारित विनिमय दर का प्रयोग अधिक उपर्युक्त होता है ।
   यह ध्यान देने योग्य है कि यू.एन.डी.पी. द्वारा शामिल किए जाने वाले सभी राष्ट्रों की सकल राष्ट्रीय आय को अमेरिकन डॉलर्स में बदला जाता है ।

4. मानव विकास सूचकांक का मूल्य 0–1 के बीच में होता है और जैसे–जैसे एक की दिशा में मानव विकास सूचकांक का मूल्य बदलता है तो यह माना जाता है कि मानव विकास बढ रहा है । मानव विकास सूचकांक 2015 के अनुसार 2014 के लिए भारत की मानव विकास सूचकांक का मूल्य 0. 609 पाया गया । भारत का मानव विकास सूचकांक मध्यम मानव विकास को प्रदर्शित करता है ।

<u>विषमता समायोजित, **(Inequality Adjusted)**</u> -

इसे वर्ष 2010 में शुरू किया गया । यह माना गया कि विषमताएँ जीवन स्तर पर विपरीत प्रभाव डालती है । ऐसी अवस्था में एच डी आई में उनका समायोजन जरूरी है।

मानव विकास सूचकांक निकालने के लिए मानव विकास सूचकांक में शामिल किए गए प्रत्येक मानव को लेकर संबंधित राष्ट्र में विषमताओं का पता लगाया जाता है एवं उनके आधार पर मानव विकास सूचकांक के मूल्य को नीचे लाया जाता है । उदाहरण के लिए यदि भारत को ध्यान में रखा जाए एवं विषमताओं को समायोजित किया जाए तो मानव विकास सूचकांक का मूल्य 0.435 आएगा (2014 के लिए) इस प्रकार विषमताओं के कारण भारत का मानव विकास सूचकांक मूल्य 28.6 % नीचे चला जाता है ।

<u>लिंग विकास सूचकांक **GDI (Gender Development Index):-**</u>

यह महिलाओं के मानव विकास को पुरुषों के मानव विकास के साथ सापेक्षिक रूप से प्रस्तुत करता है इसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है –

$$\frac{\text{HDI for Females}(0.525)}{\text{HDI for Males }(0.660)} = 0.795$$

<u>सुखी ग्रह सूचकांक **HPI (Happy Planet Index):-**</u>

मानव विकास सूचकांक मूल्य की एक मुख्य कमजोरी यह है कि इसमें उच्च जीवन स्तर के कारण पर्यावरणीय स्थिरता पर पडने वाले नकारात्मक प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा जाता । इस कमी को सुखी ग्रह सूचकांक द्वारा दूर किया गया है । सुखीग्रह सूचकांक का निर्माण नई आर्थिक नींव (यू.के.) द्वारा किया जाता है । इसे निकालने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है ।

<u>नोट</u> :-

1- ''अच्छी तरह से अनुभव किया जा रहा'' के अंतर्गत लोगों द्वारा वर्तमान कृषि के स्तर को प्रदर्शित किया जाता है A इस संदर्भ में 10 में से कोई अंक देने पडते है ।

2- पारिस्थितिकीय भोजन प्रिंट, प्राकृतिक पूँजी (Natural Capital) के उपयोग को दिखाता है जो लोग अपने वर्तमान जीवन स्तर पर कर रहे होते हैं । इसे प्रति व्यक्ति Gha(Global Hactare) में प्रदर्शित किया जाता है । यदि पारिस्थितिकीय भोजन प्रिंट का मूल्य अधिक होता है, तो सुखी ग्रह सूचकांक का मूल्य कम होगा लेकिन पारिस्थितिकीय भोजन प्रिंट जीवन स्तर के ऊँचा होने से बढेगा इस प्रकार हम कह सकते है कि जहाँ एक ओर उच्च जीवन स्तर हाल–चाल को बढाता है वहीं दूसरी ओर समग्र भूमि के स्तर पर (संदर्भ में) खुशी के स्तर को कम करता है ।

नोट – 2

1. वर्ष 2016 की रिपोर्ट में नई आर्थिक नीव द्वारा उपरोक्त मानकों में विषमताओं को भी समायोजित किया गया है ।

2- रिपोर्ट 2016 में भारत के सुखी ग्रह सूचकांक का मूल्य 29.2/100 पाया गया और भारत का इस संदर्भ में 50वां स्थान है । कोस्टारिका पहले स्थान पर है इसके द्वारा कुल ऊर्जा का 99% नवीकरणीय स्त्रोत से प्राप्त करता है । कोस्टारिका में आर्मी को हटा दिया गया तथा उस पर होने वाले खर्च को पेन्शन, स्वास्थ्य, शिक्षा की ओर मोडा गया है ।

Sustainable Development

इस शब्द का प्रयोग पहली बार 1983 में ब्रुन्डलैंड कमीशन द्वारा 1983 में हमारा सामान्य भविष्य नामक रिपोर्ट में किया गया । आयोग के अनुसार– "Inter generation equity in resource use including environment is Sustainable development."

सतत विकास शब्द को लोकप्रिय बनाने में मुख्य भूमिका 1968 में रोम का क्लब की रही है । इसके द्वारा 1972 में एम.आई.टी. वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट–विकास की सीमा को जारी किया गया जिसका सारांश यह था कि दुनिया में लगातार जीडीपी में वृद्धि नहीं की जा सकती ।

सतत् विकास के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों का अधिक प्रचार मिलता है–

1- शून्य वृद्धि (Zero Growth):- इसका भावार्थ यह है कि लिविंग स्टैण्डर्ड अधिक नहीं बढाया जाए तथा जीडीपी को एक स्तर पर बनाए रखा जाए ।

2- अनार्थिक वृद्धि Uneconomic Growth:- ऐसी वस्तुओं के उत्पादन से प्राप्त की गई वृद्धि जिनमें संसाधनों का अधिक प्रयोग हुआ है लेकिन मानव जीवन हेतु उनकी कोई विशेष उपयोगिता नहीं है ।

3- प्रतिक्षेप प्रभाव Rebound effect:- इसमें यह कहा गया कि तकनीकी का विकास होने से संसाधनों की बचत नहीं होती, बल्कि उनका अत्यधिक तेज दोहन होता है । नई तकनीकी से उत्पादकता बढती है, अधिक उत्पादकता से आय बढती है, अधिक आय से उपभोग बढता है और अधिक उपभोग के लिए अधिक उत्पादन होता है ।
भारत में हरित क्रांति के लागू होने के बाद पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में भूमि के अति दोहन को बढावा मिला ।

ग्रीन जीडीपी-
जीडीपी - जीडीपी की उत्पत्ति के क्रम में पर्यावरण को पहुँची क्षति का अनुमान या अनुमानित मूल्य ।

सकल राष्ट्रीय खुशी GNH (Gross National Happiness):-
यह अवधारणा 1972 में भूटान नरेश द्वारा दी गई ।
यह अवधारणा निम्न बातों पर आधारित है–

(कार्बन क्रेडिट)

यह एक वित्तीय इकाई होती है जो पर्यावरण से 1 टन CO_2 को हटाने के प्रयासों को प्रदर्शित करती है । इस संदर्भ में संबंधित कंपनियों या राष्ट्रों द्वारा ग्रीन प्रोजेक्ट (पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि) में निवेश किया जाता है ।

- इसी प्रकार कोई भी राष्ट्र या कंपनी क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत आवंटित किए गये AAU(Assigned Among Unit) की तुलना में CO_2 का कम उत्सर्जन करता है, तो उन्हें कार्बन क्रेडिट मिलते हैं ।
- यह ध्यान देने योग्य है कि एक AAU 1 टन CO_2 ;k CO_2e को पर्यावरण में उत्सर्जित करने की छूट देता है ।
- यदि कोई राष्ट्र आवंटित AAU की तुलना में अधिक उत्सर्जन करता है तो उसे कार्बन क्रेडिट खरीदने होंगे या स्वच्छ प्रौद्योगिकी में निवेश करना होगा ।
- इस प्रकार कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उन कंपनियों के लिए प्रेरक होती है जो अधिक प्रदूषण करती है एवं उनके लिए प्रेरक होती है जो कम प्रदूषण करती है । उपभोक्ताओं द्वारा अपने आप कम कीमतों के माध्यम से उन वस्तुओं द्वारा खरीदा जाएगा जिनका उत्पादन स्वच्छ प्रौद्योगिकी के माध्यम से हो रहा है ।
- कार्बन क्रेडिट का व्यापार भी किया जाता है । भारत में पहली बार MCX, (Multi Commodity Exchange) मुंबई द्वारा शुरू किया गया था ।

<u>कार्बन टैक्स</u> :-
प्रदूषण कारी वस्तुओं के उत्पादन या उनके विक्रय पर लगाए जाने वाले करों को कार्बन टैक्स कहा जाता है इनके माध्यम से उत्पाद मूल्य निर्धारण पर्यावरणीय लागत लाया जा सकता है जो सामान्यतः बाजार नहीं कर सकते हैं ।
इको सर्वे 2016–17 – भारत एकमात्र राष्ट्र है जो कोयले पर कार्बन टैक्स लगाता है । भारत इसे स्वच्छ पर्यावरणीय उपकर के नाम से आरोपित करता है ।

<u>ग्रीन बॉण्ड</u> :-
कंपनियों और संस्थाओं द्वारा निकाले जाने वाले ऐसे बॉण्ड जिनसे प्राप्त की गई धनराशि का प्रयोग ग्रीन प्रोजेक्ट में किया जाता है ।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड बैंक इस प्रकार के बॉण्ड को प्रोत्साहित कर रहा है । बॉण्ड के द्वारा कंपनियों आदि निवेशकों से ऋणों के रूप में पूँजी एकत्र करते हैं ।

<u>ग्रीन मसाला बॉण्ड</u> :- विदेशों में भारतीय कंपनियों, बैंकों आदि के द्वारा जारी किए जाने वाले रूपी अस्वीकृत बॉण्ड को मसाला बॉण्ड कहते हैं यदि मसाला बॉण्ड से प्राप्त धन का प्रयोग ग्रीन प्रोजेक्ट में किया जाता है तो ऐसे बॉण्ड को ग्रीन मसाला बॉण्ड कहते हैं । एचडीएफसी द्वारा 2016 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर इन बॉण्ड को लिस्ट करवाया गया । इस संदर्भ में एचडीएफसी भारत की पहली कंपनी है ।

यह ध्यान देने योग्य है कि IFC द्वारा सबसे पहले ग्रीन मसाला ब्रॉड का s LSE पर लिस्ट करवाया गया । विदेशी सरकारों द्वारा भी इन्हें निकाला जा सकता है । वर्ष 2016 में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांतीय सरकार द्वारा इन्हें निकाला गया ।

Greenex:-

यह बी.एस.ई. से जुडा हुआ एक शेयर सूचकांक है जो ऊर्जा दक्षता में सबसे अग्रणी 25 कंपनियों के शेयर मूल्यों को शामिल करता है । इसे 2012 में शुरू किया गया था इसकी आधार तिथि 1 अक्टूबर 2008 मानी गई । इस तिथि को इसका मूल्य रू. 1000 माना गया ।

Environmental Kuznets Curve :-

इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है –

प्रदूषण असमानता (Pollution/Inequality)

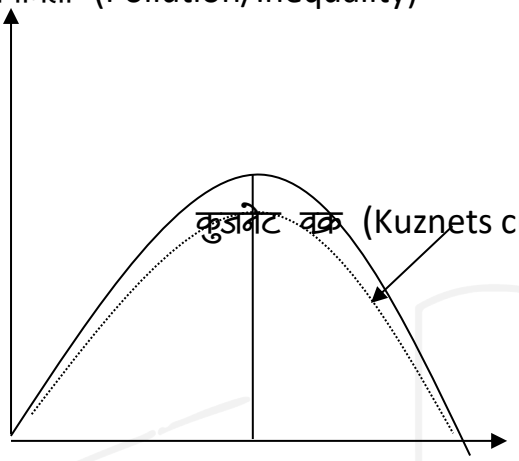

0 x_0 विकास का स्तर (Level of Development)

उपर्युक्त वक्र से यह पता लगता है कि PCI का x_0 स्तर तक विकास के साथ–साथ प्रदूषण बढता है लेकिन x_0 के बाद में विकास के साथ प्रदूषण कम होने लगता है ।

अधिकांश विकासशील राष्ट्रों में पर्यावरण से संबंधित नियमों को ढीला रखा जाता है ताकि औद्योगिक विकास को बढावा मिले इससे आरंभिक दौर में प्रदूषण बढने लगता है ।

आर्थिक समस्याओं से जुडे कुछ महत्वपूर्ण शब्द –

1- कम गति (Slow Down)

इसमें जीडीपी की ग्रोथ रेट कम हो जाती है लेकिन वह सकारात्मक बनी रहती है । कम गति में जीडीपी बढती है लेकिन बढने की दर कम हो जाती है ।

जैसे–

	t_1	t_2	t_3
GDP 100 तो	105	108	110
	5%	3%	1.5%

जैसे – भारत में 2015–16 में जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6% रही जबकि 2016–17 में इसके 7% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है ।

2- संकुचन **(Contraction)**

इसमें जीडीपी कम होने लगता है । जब किसी वर्ष की पहली तिमाही में पहली बार वृद्धि दर, नकारात्मक हो जाती है तो इसे संकुचन कहते है ।

जैसे –

2016&17	2015&16
Q1(Apr-June)5%	Q1
Q2 3%	Q2
Q3	Q3
Q4	Q4

3- मंदी (Recession)

जब किसी देश में, किसी वर्ष में लगातार कम से कम 2 तिमाही के लिए जीडीपी की वृद्धि दर नकारात्मक बनी रहती है, तो इस स्थिति को मंदी कहा जाता है ।

2016–17	2013–14	2016–17	2015–16
Q1 3%	Q1	Q1 3%	Q1
Q2 2%	Q2	Q2 2%	Q2
Q3 1%	Q3	Q3 1%	Q3
Q4	Q4	Q4	Q4

4- मंदी (Depression)

इसमें रोजगार के गुण रहते हैं लेकिन उसके साथ–साथ वस्तुओं की कीमतें गिरने लगती है । इसमें मंदी के साथ वस्तुओं की कीमतें गिरने लगती हैं अर्थात् मंदी में मंदी + अपस्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । यह स्थिति काफी गंभीर होती है क्योंकि इसमें बेरोजगारी फैलने लगती है। इस अवस्था में बेरोजगारी तेज अवस्था में बढती है जिसका मुख्य कारण वेज स्टीकनेस होता है जो नीचे की ओर होता है ।

इसमें मंदी के साथ वस्तुओं की कीमतें गिरने लगती है । अर्थात् मंदी में मंदी + अपस्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । यह स्थिति काफी गंभीर होती है । क्योंकि इसमें बेरोजगारी फैलने लगती है ।

Price are Inflexible
Wages are not flexible

5- मेल्ट डाउन :-

शेयर बाजारों का तेज गति से गिरना अर्थात् किसी देश में वित्त बाजार तेज गति से गिरने लगे तो इस स्थिति को मेल्ट डाउन कहा जाता है ।

प्रोत्साहन (Stimulus):-

एक अर्थव्यवस्था को स्लो डाउन, संकुलन, मंदी आदि स्थितियों से बाहर निकालने के लिए सरकार की ओर से दिया जाने वाला मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों का एक मिलाजुला पैकेज । यह समग्र राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाता है इस प्रकार यह बेल आउट से अलग होता है जो विशेष कंपनियों अथवा क्षेत्रों पर लागू किया जाता है । अमेरिका जैसे राष्ट्रों में प्रोत्साहन एवं बेल डाउन दोनों का प्रयोग किया जाता है ।

मुद्रा एक बाकेट या स्टोर है ।

भारत देश राष्ट्रों में प्रोत्साहन एवं बेल आउट दोनों का प्रयोग किया जाता है जबकि भारत जैसे राष्ट्रों में सामान्यतः प्रोत्साहन का प्रयोग किया जाता ।

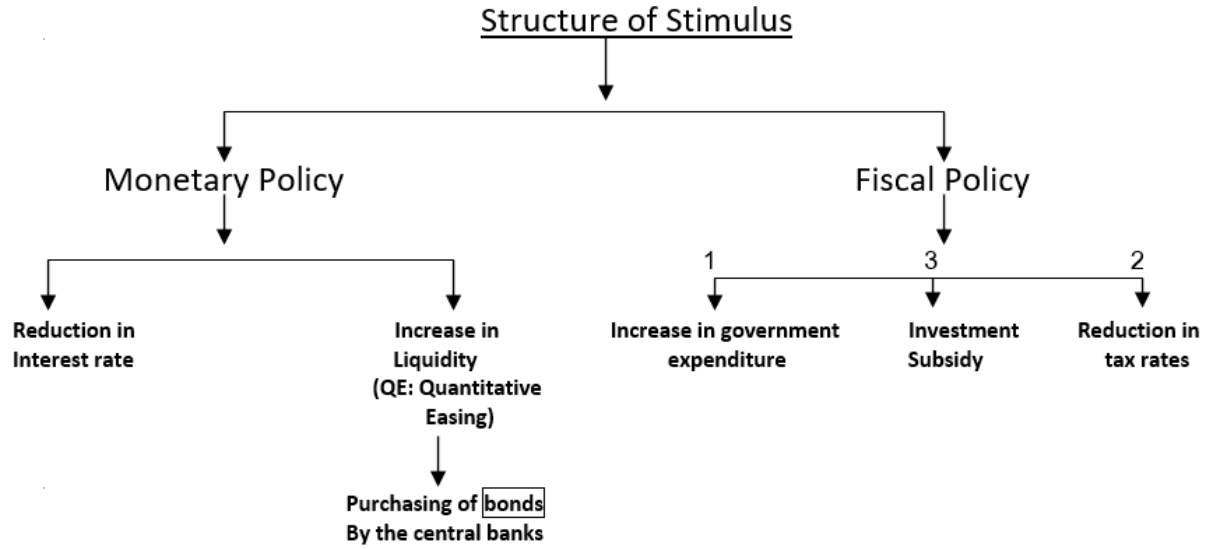

GDP का समग्र माँग दृष्टिकोणः–

कींस के अनुसार मंदी का कारण समग्र माँग में कमी होता है, उनके अनुसार समग्र माँग ही जीडीपी को निर्धारित करता है।

1. कींस के अनुसार जीडीपी, रोजगार आदि का स्तर समग्र माँग पर निर्भर करता है ।

समग्र माँगः

AD= C + I + G + (X-M) ∴ X-M→N×(Net export)

NX

C= उपभोग– लोगों द्वारा संतुष्टि के लिए किया जाने वाला एक खर्च ।

I= निवेश– उत्पादन क्षमता बढाने के लिए किया जाने वाला खर्च ।

G= Government Expenditure for Social Welfare

X= निर्यात /Export– विदेशी लोगों द्वारा स्वदेशी वस्तुओं पर किया जाने वाला खर्च ।

M= आयात /Import– स्वदेशी लोगों द्वारा विदेशी वस्तुओं पर किया जाने वाला खर्च ।

नोट :-

1. लोगों की आय एवं उपभोग में सीधा संबंध होता है लेकिन आय में परिवर्तन की तुलना में उपभोग में कम परिवर्तन होते हैं । इसका कारण यह होता है कि लोगों द्वारा आय के एक भाग की बचत कर ली जाती है ।
2. निवेश एवं ब्याज दर के बीच में विपरीत संबंध होता है, इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है–

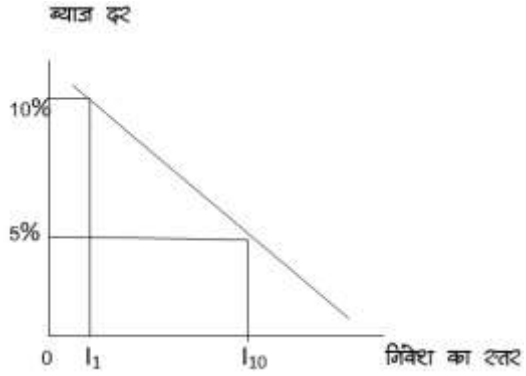

उपर्युक्त चित्र से यह पता लगता है कि ऊँची ब्याज दरों पर निवेश का स्तर कम हो जाता है । जबकि निम्न ब्याज दर पर निवेश का स्तर ऊँचा होता है । यह ध्यान देने योग्य है कि स्लो डाउन रिसेशन आदि में निवेश की कम ब्याज दरों के प्रति प्रतिक्रिया कमजोर हो जाती है । तकनीकी शब्दों में निवेश अलचकदार हो जाता है जिसके कारण मौद्रिक नीति की भूमिका कमजोर हो जाती है इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है –

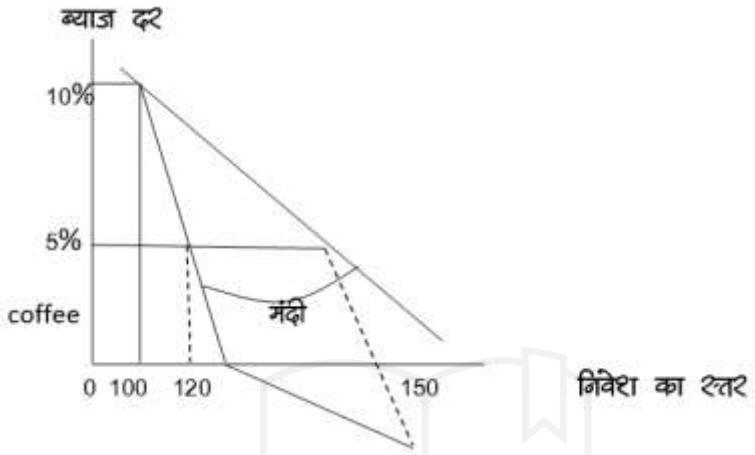

उपरोक्त स्थिति से निपटने के लिए सरकार राजकोषीय नीति के अंतर्गत निवेश सब्सिडी का प्रयोग कर सकती है । निवेश सब्सिडी के कारण सभी ब्याज दरों पर निवेश का स्तर ऊँचा हो सकता है ।

नोट :- यदि किसी भी प्रकार से निवेश ठीक से नहीं बढता है । तो सरकार अपने खर्चों को बढा सकती है विशेष रूप से अनुवादक खर्चों को& 7th Pay Commission, Universal Basic Trans.

उपर्युक्त के अलावा, सरकार द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों को कम किया जा सकता है । प्रत्यक्ष करों को कम करने से लोगों की खर्चे योग्य आय बढती है, जबकि अप्रत्यक्ष करों को कम करने से वस्तुओं की कीमत कम होती है जिससे माँग बढ सकती है ।

बंद अर्थव्यवस्था **(Closed Economy)** :-

यदि कोई अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करती तो उसे बंद इकोनॉमी या क्लोसो इकोनॉमी कहा जाता है इसे थ्री सेक्टर इकोनोमी भी कहते हैं क्योंकि इसमें समग्र माँग का निम्न सूत्र प्रयुक्त होता है ।

AD = C+ I + G

खुली अर्थव्यवस्था **(Open Economy)**:-

जो अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करती है, उसे ओपन इकोनोमी कहते हैं इसे चार सेक्टर इकोनॉमी भी कहते हैं क्योंकि इसमें समग्र माँग निम्न प्रकार होती है –

AD = C + I + G + (X-M)

– एक खुली अर्थव्यवस्था में जीडीपी एवं आयातों के बीच में सीधा संबंध होता है इसका निहितार्थ हुआ कि यदि कोई राष्ट्र जीडीपी बढाता है तो इसे बढे हुए आयामों का सामना करना पडता है ।

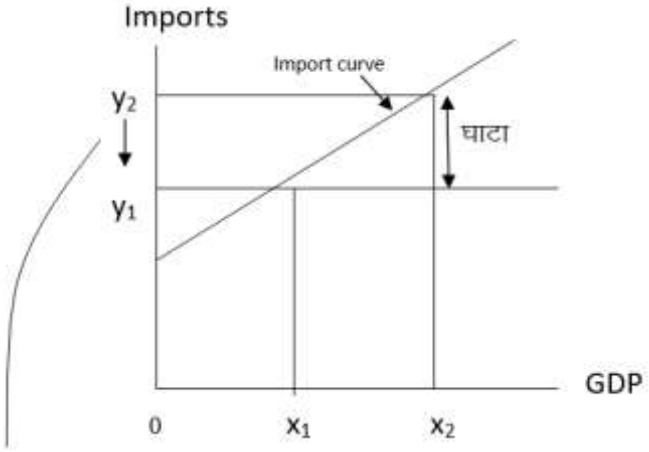

अमेरिका का आयात घटा – जिससे हमारा निर्यात प्रभाव 2008 में हीरा उद्योग में मंदी – एल.पी.जी. के माध्यम से जीडीपी निर्यातों को प्रभावित नहीं करता हालाँकि निर्यात जीडीपी को प्रभावित करते हैं ।
7% पश्चिमी GDP में योगदान निर्यात करें क्यों Gap - USA GDPA, निर्यात

U.P.S.C.

यदि कोई राष्ट्र निर्यातों को केंद्र में रखकर जीडीपी को बढावा देता है, तो इसे निर्यात के नेतृत्व वाला कहा जाता है। इस मॉडल का प्रयोग चीन द्वारा एक लंबे समय तक किया गया लेकिन इसे बडी अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अधिक समय तक उचित नहीं माना जाता। चीन हाल ही में खपत का नेतृत्व किया विकास मॉडल की ओर चला गया । कुछ सीमा तक भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को इस मॉडल का पश्चायक माना जा सकता है ।

इस मॉडल के चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भी रघुराम राजन द्वारा यह कहा गया कि भारत के लिए मेक इन इंडिया अधिक उपर्युक्त होगा । यह ध्यान देने योग्य है कि विश्व अर्थव्यवस्था में कमजोरी आती रहती है तथा अधिकांश राष्ट्र संरक्षणवादी नीतियों का प्रयोग करते है जैसा कि ट्रंप द्वारा खरीद अमेरिकी और उच्च अमेरिकी के नारे का प्रयोग किया गया ।

- यदि कोई राष्ट्र संवृद्धि को बढावा देता है, तो उसके कारण आयात बढता है । यदि बढते हुए आयतों का मुकाबला करने के लिए निर्यातों को प्रोत्साहित किया जाता है तो इसे विकास के निर्यात का नेतृत्व मॉडल कहते है ।

सरकारी घाटे

1. राजस्व घाटा **(Revenul Deficit):-**
   कुल राजस्व खर्चों का कुल राजस्व प्राप्तियो पर आधिक्य राजस्व घाटा कहलाता है । केन्द्रीय बजट 2017–18 में इसका अनुमान जीडीपी के 1.9 प्रतिशत पर लगाया गया है ।

2. पूँजीगत घाटा **(Capital Deficit):-**
   कुल पूँजीगत खर्चों का कुल पूँजीगत प्राप्तियों पर आधिक्य पूँजीगत घाटा कहलाता है ।

3. **राजकोषीय घाटा (Fiscal deficit):-**

दूसरे शब्दों में, राजकोषीय घाटा कुल खर्चो (राजस्व पूँजीगत) का कुल प्राप्तिओं पर आधिक्य होता है जबकि पूँजीगत प्राप्तिओं में बाजार से उधार एवं देयताओ को शामिल नहीं किया । इस विषय पर गठित रंगराजन समिति द्वारा इस बात की सिफारिश की गई थी । 14वें वित्त आयोग द्वारा भी इस वर्गीकरण को समाप्त करने को कहा गया था । प्लान और नॉन प्लान के वर्गीकरण को निम्न प्रकार दिखाया जा सकता है –